

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
शहरी विकास निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 09 सितम्बर, 2016

विषय: "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत नगर निकायों में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 968/IV(2)-श0वि0-45(सा0)-2015, दिनांक 11.08.2015 एवं संख्या: 1607/IV(2)-श0वि0-45(सा0)-2015, दिनांक 15.12.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत विभिन्न मदों में कुल ₹712.30 लाख की धनराशि अमवुक्त की गयी है।

2- उपरोक्त के क्रम में आपके पत्र संख्या: 317/श0वि0नि0/स्व0भा0मि0/2015-16, दिनांक 23.07.2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: 1/18/2015-SBM, दिनांक 01.07.2016 द्वारा "स्वच्छ भारत मिशन" के उपघटकों "व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण" एवं "सामुदायिक शौचालयों का निर्माण" हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि कुल ₹277.00 लाख (रुपये दो करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) की निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

SBM के अन्तर्गत मद	स्वीकृत शौचालयों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (केन्द्रांश)
Construction of Individual household latrines (IHHL)	6250	125.00 (द्वितीय किस्त)
	5000	100.00 (प्रथम किस्त)
Community Toilet	200	52.00 (40%)
Total-		277.00

2- उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

- उक्त धनराशि कुल ₹277.00 लाख (रुपये दो करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर योजनान्तर्गत चयनित नगर निकायों को बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर दिया जाय कि पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।
- "स्वच्छ भारत मिशन" हेतु भारत सरकार द्वारा जारी Guideline एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।
- स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

- (vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।
- (vii) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- (viii) परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
- (ix) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा।
- (x) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
- (xi) स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- (xii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (xiii) निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी
- (xiv) पूर्व निर्गत शासनादेशों क्रमशः दिनांक 11.08.2015 एवं 18.12.2015 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xv) धनराशि की स्वीकृति/उपयोग के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 एवं संख्या: 965/XXVII(1)/2016, दिनांक 19.08.2016 में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xvi) धनराशि का दिनांक 31-3-2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूपों पर शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय के अनुदान सं०-13, लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना-10-स्वच्छ भारत मिशन-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के संख्या:847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में निहित व्यवस्थानुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्न-एलॉटमेन्ट आईडी 0 s...16.09.130.182

भवदीय,

(नितिन सिंह भदौरिया)  
अपर सचिव।

संख्या-1568 (1)/IV(2)-शा०वि०-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अधिकारी, आईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आह्वा से,

( गजेन्द्र सिंह कफलिया )  
अनु सचिव।